राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 28 अंक : 3 मई 2005

- दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रवेश पर विशेष
- लेख : गिरावट की ओर उच्च शिक्षा
- चुनौती : जनसंख्या असंतुलन का खतरा
- Struggle of Rai University Students for their Degrees

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 28 अंक : 3, मई 2005

मुख पृष्ठ

अ.भा.वि.प., राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित मॉडल प्रदर्शनी 'अभिव्यक्ति–2005' का उद्घाटन समारोह। दीप प्रज्ज्वलित करते प्रदर्शनी संयोजक डा. एन.पी. कौशिक, साथ में हैं डा. एच.डी. चारण (संयोजक, TSVP) हीतेन्द्र शर्मा (महानगर मंत्री ABVP कोटा) डा. बी.एल शर्मा (उपकुलपति, कोटा विश्वविद्यालय) एवं प्रा. एस.एस. तोमर।

प्रकाशक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
बी–50, क्रिश्चियन कालोनी,
निकट पटेल चेस्ट हॉस्पिटल,
दिल्ली–110007
फोन : 011 – 27666019, 27662477

Website : www.abvp.org

कार्टून कोना

साभार : दैनिक जागरण

संवाद / साक्षात्कार
विचारधारा / वैचारिकी
मत - सम्मत

अनुक्रम

सम्पादकीय
छात्रसंघ प्रतिबंध पर पुनर्विचार जरूरी..... 3

शैक्षिक परिदृश्य
गिरावट की ओर उच्च शिक्षा..... 4
–डा. हरिप्रसाद दुबे

राष्ट्रीय परिदृश्य
जनसंख्या असंतुलन का खतरा..... 6
–जितेन्द्र बजाज

डा. हेडगेवार एवं डा. अम्बेडकर जयंती
दो महानायक : लक्ष्य एक..... 8
–डा. विजय सोनकर शास्त्री

Students Movement
Struggle of Rai University Students..... 10

परिषद गतिविधियां..... 12
विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया : 2005–06..... 15

कविता

धार करो पार

राष्ट्र धर्म नौका के
युवा–शक्ति कर्णधार।
धार करो पार।
झंझावात मुख मोड़े,
गति, जलावर्त तोड़े,
लक्ष्य–पुलिन निकट आए
आश–दीप जगमगाये
देश–भक्ति की लो पतवार।
तुम चरित्र–पूत हो,
क्रांति अग्रदूत हो,
संकट की वेला है,
अवमूल्यन–मेला है
मुट्ठी में आगत हो
अधरों पर स्वागत हो
खोलो, रूढ़ संस्कृति के द्वार।

–डा० शम्भूनाथ चतुर्वेदी

छात्र संघ प्रतिबंध पर पुनर्विचार जरूरी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 मई, 2005 को दिए अपने निर्णय के तहत प्रदेश में कॉलेज/विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश की सर्वत्र आलोचना हो रही है। विभिन्न राजनैतिक–सामाजिक संगठनों के साथ–साथ सभी छात्र संगठनों ने इस आदेश पर अपनी असहमति जताई है। विद्यार्थी परिषद ने भी इस निर्णय को अनुचित बताते हुए कहा है कि छात्र संघ चुनावों पर रोक की बजाय व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हम गर्व के साथ कहते है कि भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है। यह अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होता है कि एक तरफ तो आप 18 वर्ष की उम्र के छात्र–युवकों को वोट देने का अधिकार देते है और वहीं दूसरी ओर राजनीति में लिप्तता को आधार मानकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाते है। आज जब समाज–जीवन और राष्ट्रीय राजनीति में भी विकृतियां दिखाई दे रही है तो उसका प्रतिबिम्ब छात्र राजनीति पर भी पड़ता है। भारत में छात्र संघों का एक गौरवमयी इतिहास है। जब देश को आपातकाल की ओर धकेल दिया गया तो उससे लड़ने सामने कौन आया ? सबको मालूम है कि उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अरूण जेटली (विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता) के संयोजकत्व में देशभर के छात्रों ने लम्बी लडाई लडी। जिसके परिणामस्वरूप न केवल आपातकाल खत्म हुआ बल्कि सत्तामद में चूर केन्द्र सरकार की चूलें भी हिल गई। यह सुविदित है कि छात्र संघ से निकले अनेक नेता राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में अन्य की अपेक्षा अच्छी भूमिका निभा रहे है। न्यायालय का यह कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि छात्र संघ के कारण विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जानेवाली उपाधियां हेय दृष्टि से देखी जाती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जहां प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव होते है, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देशभर में सर्वोच्च स्थान पर है।

देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 'जनसत्ता' का कहना है कि छात्र संघ का चुनाव लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। इनके न होने से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में प्रशासन के गलत या मनमाने फैसलों पर अंकुश लगाने की गुंजाइश खत्म हो जायेगी।

न्यायालय के मुताबिक मेरिट में आनेवाले छात्रों को यदि छात्र संघ पदाधिकारी बनाया गया तो यहां प्रश्न उठता है कि यह समस्याओं को कैसे दूर कर पायेगा ? क्योंकि वह तो हमेशा पढ़ाई में ही लगा होगा और फिर यह जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान में पारंगत छात्र में सक्षम नेतृत्व के गुण हो ही। यह व्यवस्था कहीं से भी व्यवहारिक नहीं दिखता।

इसलिए इस पूरे मामले में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद की यह चिरलम्बित मांग रही है कि छात्र संघ चुनाव पर एक व्यवहारिक आचार संहिता बने और उसका कड़ाई से पालन हो, तभी कोई सार्थक परिणाम सामने आयेंगे।

- देश की राजधानी दिल्ली में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके अगले ही दिन नॉर्थ कैम्पस में एक और छात्रा छेड़छाड़ की शिकार हो गई। आवश्यकता इस बात की है कि कैम्पसों में गठित यौन उत्पीड़न विरोधी कमिटी को सशक्त व प्रभावी बनाया जाय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
- इस अंक में "गिरावट की ओर उच्च शिक्षा" विषय पर एक विचारोत्तेजक लेख दिया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती "जनसंख्या असंतुलन का खतरा" को रेखांकित करने के लिए सुप्रसिद्ध लेखक जितेन्द्र बजाज का लेख भी छाप रहे है।
- देशभर में विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। उनमें से कुछ प्रमुख गतिविधियां आपके समक्ष प्रस्तुत है।

इस अंक से पत्रिका की प्रस्तुति में हम नयापन ला रहे है। विश्वास है कि आपको यह अंक बेहद पसंद आयेगा।

परीक्षा एवं नए सत्र की शुभकामनाएं सहित

वन्दे मातरम्।

गिरावट की ओर उच्च शिक्षा

डॉ० हरिप्रसाद दुबे

विश्व गुरू के पद से विभूषित भारतीय शिक्षा ज्ञान, चरित्र और संस्कृति जैसे तत्वों से संवर्द्धित हुई। मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी हमारे जीवन मूल्यों को क्षीण करके हमें अपने मूल में ही भटका रही है। शिक्षा में राष्ट्रीय बोध के बिना देश का सर्वांगीण उत्थान, सामाजिक समरसता और अखंडता का विकास असंभव है।

समाज और देश की उन्नति बिना उच्च कोटि की शिक्षा के असंभव है। इसका आधार हमारा नैतिक अधिष्ठान है, जिसकी रक्षा और संवर्द्धन करना शिक्षा का मूलमंत्र है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में उच्च शिक्षा में परिवर्तन के उद्देश्य से अनेक आयोग और समितियां गठित हुई, किंतु प्रभावित नहीं कर पाई। आदिकाल से किसी भी युग में भारतीय शिक्षा का लक्ष्य मानव को संयमी और शिष्ट बनाना रहा है। शिक्षकों का गुरू–स्वरूप ईश्वर से भी उच्चता पर माना गया। राष्ट्र के विकास में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारी गई है। शिक्षा व्यवस्था में आई विकृतियों के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को विशेष दोष दिया जाता है। उसमें भी अध्यापकों द्वारा दायित्व निर्वहन न करने का मूल कारण कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्वरूप, विकास और सुधार के लिए गठित एकमात्र संस्था है। प्राध्यापकों की नियुक्तियों के लिए पूरे देश में समान मानकों का क्रियान्वयन करना इसका महत्वपूर्ण अंग है।

विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण की आधारभूमि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग–अलग प्रांतों में की जा रही अवैधानिक मनमानी रोकने में विफल सिद्ध हुआ है। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक नं लगने से समूचे देश की उच्च शिक्षा की स्थिति चिंतनीय होती गई है। भेदभाव, वर्ग–भेद और अनुशंसा के आधार पर पद प्राप्त कर रहे शिक्षक योग्य और परिश्रमी अध्येताओं का अवसर छीनने में लगे हैं। देश में आदर्श, निष्ठावान शिक्षकों ने जो त्याग का पथ दिखाया वह आज विलुप्त है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है "शिक्षा की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है और यही हमारे अधःपतन का कारण भी है।" आचार्य नरेंद्र देव ने कुलपति जैसे पद पर रहते हुए गरीब विद्यार्थियों को अपने आवास में शरण दी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदनमोहन मालवीय ने वि.वि. में कई वर्षों तक अवैतनिक अध्यापन करते हुए विश्वविद्यालय की नियमावली में भी लिखा है "मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं रह सकता।" आज मालवीय जी के पदचिन्हों पर चलने वाले कितने है? उच्च शिक्षा के लिए जिस प्रारंभिक शिक्षा का अंकुर कृष्णचंद्र गांधी ने बोया, यह उनकी निष्ठा का ही परिणाम है कि आज देश में 22 हजार विद्यालय है। समाजसेवी नाना जी देशमुख ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही आदिवासी छात्रावास भी स्थापित कराए।

उच्च शिक्षा के विकास में समाजसेवा की भावना में जाति, वर्ग और भेद से दूर होकर किया गया कार्य ही जीवंत बनता है।

राष्ट्रपति डॉ. कलाम वर्ष 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे है, लेकिन देश की युवा प्रतिभाओं को नियुक्तियों से वंचित करने की गुप्त योजनएं फल–फूल रही हैं। अभी हाल में ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय में जैन पीठ के रीडर पद पर सेवानिवृत्त प्राध्यापक को नियुक्त करके नई पीढ़ी के योग्य अभ्यार्थियों को अवसर से वंचित कर दिया गया। ऐसा करना तब उचित था जब नई पीढ़ी का कोई योग्य शिक्षक न मिलता। अनुशंसा के आधार पर देश में की जा रही नियुक्तियों से उच्च शिक्षा का क्षेत्र पतनोन्मुखी है, सबसे बडे प्रदेश उत्तर प्रदेश की स्थिति उच्च शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत दयनीय है। अशासकीय महाविद्यालयों के रिक्त प्राध्यापक पदों पर बिना विज्ञापन और साक्षात्कार कराये 1993–94 में फर्जी नियुक्तियों की हेराफेरी आज तक नहीं खुल पाई है। उ.प्र.

उच्चतर शिक्षा, सेवा आयोग ने वर्ष 2001 में जो नियुक्तियां की थीं उनमे हेराफेरी का आरोप लगा था। सेवनिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर पुनः पद दिये जाने के पीछे युवा पीढी के अधिकार छीनने के अलावा और क्या कारण हो सकते है? इससे तो यह अच्छा होता कि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा सत्तर वर्ष कर दी जाए या नेताओं की भांति उन्हें आजीवन पद पर रखा जाए। एक तरफ पेंशन, दूसरी तरफ मानदेय का वेतन क्या दोहरे लाभ मे नहीं आता? अपने व्यक्तिगत संसाधनों से 1993 तक पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त युवा पीढ़ी को नकार कर पांच वर्षों तक प्राथमिक शिक्षक के वेतनमान जैसी शोध अध्येता वृत्ति प्राप्त करने वालों को नियुक्तियों में वरीयता देने के पीछे भेदभाव प्रमुख है।

विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में सम्मिलित कतिपय विभागाध्यक्ष स्वयं तो अभ्यर्थियों के शोध कार्यों की चोरी करके अपने नाम से प्रकाशित कराने का अपराध करते हैं और दूसरी ओर उस अभ्यर्थी के पद पर आने में बाधा डालते हैं। साक्षात्कार समितियां एक ही दिन में विश्वविद्यालय में पिता को प्रोफेसर और संतान को प्रवक्ता पद प्रदान कर देती हैं। शोध और श्रम शून्य बन जाता है। बिहार में अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां शिक्षकों का पूर्ण अभाव है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के जीवन पुराण शिक्षा जगत को चकित करने वाले हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में आई.पी.एस. अधिकारी भी कुलपति के पद पर पहुंच चुके है। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा में अन्य प्रांतों से पृथक मानक रखे गये है। आयु सीमा के अंतर के कारण उच्च शिक्षा की नियुक्तियों में असमानता आती गई है। जब तक यू.जी.सी. का मानक पूरे देश में लागू नहीं होता, उच्च शिक्षा में सुधार असंभव है। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी पीछे नहीं है। प्राध्यापकों के रिक्त पदों का विज्ञापन जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष कई बार कराते हैं, वहीं साक्षात्कार कराने में अचानक इतनी तत्परता कर बैठते हैं कि योग्य से योग्य अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र के समय से न मिल पाने के कारण साक्षात्कार के अवसर से वंचित हो जाते है। निजी क्षेत्रों मे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना से शिक्षकों की नियुक्तियां व्यावसायिक हो रही है। यहां कम वेतन में अयोग्य शिक्षकों का चयन प्राथमिकता पर है। वर्तमान में शिक्षा की मौलिकता अर्थ की मौलिकता में खो गई है।

पाठ्यक्रम निर्धारित करने में जब तक योग्य और अध्यवसायी प्राध्यापकों का वर्चस्व नहीं होगा, तब तक उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं किया जा सकता। चूंकि योग्य शिक्षकों द्वारा ही योग्य छात्रों का निर्माण होता है, अतः सारा दोष छात्रों पर ही देना अनुचित है। शिक्षा के स्तंभ स्वरूप प्राध्यापकों की नियुक्तियों में ही जब भ्रष्टाचार और हेराफेरी का समावेश है तो इक्कीसवीं सदी की शिक्षा की नींव कैसे सुदृढ होगी? योग्य शोध-अध्येताओं को जब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक पद के लिए अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो वे अपनी विषय दक्षता कैसे दिखायेंगे? योग्यता का आधार अनुशंसा का ही होने पर देश की उच्च शिक्षा का शिखर पर पहुंचना असंभव है। इसीलिए विश्व के श्रेष्ठ 20 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है।

(साभार : दैनिक जागरण) ■

प्रेरणा

छात्र की निर्भीकता

पंजाब के एक अंग्रेजी स्कूल में एक अंग्रेज अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था। उसने कहा, 'प्राचीन भारत के लोग जंगली और असभ्य थे। वे पेड-पत्थरों को पूजते थे। अंग्रेजों ने उन्हें यहां आकर सभ्य बनाया।'

हंसराज नामक छात्र अपने देश की बुराई सहन नहीं कर पाया। उसने तुरंत खडे होकर कहा, 'सर, आपकी यह बात सच नहीं है। भारतीय सर्वव्यापी एक ही ईश्वर की विविध रूपों में पूजा करते हैं। भारतीय जंगली नहीं, बल्कि बहुत विद्वान थे। हमारे ऋषि-मुनि ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता थे।' अध्यापक ने क्रोध में भरकर उस छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दिया। शिक्षक के शब्दों ने हंसराज के हृदय को झकझोर डाला। आगे चलकर यही हंसराज आर्य समाज के संपर्क में आकर उच्च कोटि के संत बने। उन्होंने भारतीयता पर आधारित शिक्षा के प्रचार के लिए लाहौर में दयानंद विद्यालय की स्थापना की।

महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित विद्यालय आज भी शिक्षा के प्रचार में योगदान कर रहे हैं। ■

जनसंख्या असंतुलन का खतरा

–जितेन्द्र बजाज

भारत में 1871 से ही जब जनगणना का कार्य शुरू हुआ, तभी से पंथानुसार आंकड़ें इकट्ठे किए जाते रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक विषयों का भी पंथानुसार आंकलन किया जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व पंथानुसार शिक्षा, लिंगानुपात, आर्थिक व्यवसाय आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद यह बंद कर दिया गया। इस कारण वस्तुस्थिति का पता नहीं चल पाता था, आंकड़ा मिल जाता था, लेकिन सामाजिक–आर्थिक स्तर पर क्या हो रहा है, यह लोगों के सामने नहीं आंता था। हालांकि जनगणना के दौरान ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। अब पहली बार जनगणना के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण कर व्यवसाय, शिक्षा, लिंग के अनुरूप वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। ये आंकड़े सामने आने के बाद अनेक गुत्थियों को सुलझाने और समझने में मदद मिल सकेगी।

जनसंख्या असंतुलन के सामाजिक कारण

पहले लोगों का अनुमान था कि हिन्दू, मुस्लिम और ईसाइयों की आबादी बढ़ने या घटने में आर्थिक–सामाजिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। लेकिन इस बार जनगणना के विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों कारण बहुत अधिक भूमिका नहीं निभाते। माना जाता था कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि का कारण उनका आर्थिक पिछड़ापन और अशिक्षा है। आंकड़े देखें तो स्पष्ट है कि हिन्दुओं और मुसलमानों की साक्षरता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। हिन्दुओं की साक्षरता दर 55 प्रतिशत है तो मुसलमानों की 47 प्रतिशत। इसी प्रकार 45 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं साक्षर हैं तो मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मुसलमानों में जन्म दर बढ़ने का कारण उनमें अशिक्षा है।

खतरे की घंटी

1901 से 2001 तक 100 साल में हुई जनगणनाओं के आंकड़े देखें तो चिंताजनक तथ्य सामने आता है कि 1947 से पूर्व के भारत वर्ष (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश) में भारतीय मूल के पंथावलम्बियों के अनुपात में तेजी से कमी आयी है। 1881 में यहां की जनसंख्या में भारतीय मूल के पंथावलम्बियों का अनुपात 79.32 प्रतिशत था, 1991 में यह घटकर 68.03 प्रतिशत रह गया। इसकी तुलना में मुसलमानों का अनुपात प्रायः 10 अंकों तक बढ़ा है। 1881 में उनकी जनसंख्या का अनुपात 19.97 प्रतिशत था, जो 1991 में 29.94 प्रतिशत हो गया। ईसाइयों का अनुपात 1 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ा है। 1881 में वे जनसंख्या का 0.79 प्रतिशत थे, 1991 में 2 प्रतिशत से अधिक हो गए। अगर सिर्फ भारत की स्थिति पर नजर डालें तो हिन्दुओं की घटती जनसंख्या स्पष्ट रूप से खतरे का संकेत देती है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई जनगणना में हिन्दुओं का अनुपात 87.24 प्रतिशत था, जो 2001 तक यानी पांच दशकों में घटकर 84.21 प्रतिशत रह गया। अर्थात् 3 प्रतिशत हिन्दू घटे जबकि मुसलमानों का अनुपात 10.43 प्रतिशत था। जो 2001 में बढ़कर 13.43 प्रतिशत हो गया। अर्थात् 3 प्रतिशत की वृद्धि। इसी प्रकार ईसाइयों के अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई। 1951 में ईसाई जनसंख्या का अनुपात 2.33 प्रतिशत था, जो 2001 में 2.35 प्रतिशत हो गया। भारत–विभाजन के बाद इतना बड़ा अंतर चिंता की बात है।

चिंता क्यों?

अगर राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक इकाई बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है तो पंथानुसार जनसंख्या के अनुपात में यह अंतर भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भारत की एकता महत्वपूर्ण है तो यह अनुपात भी महत्वपूर्ण है। जिन देशों को अपनी आंतरिक एकता महत्वपूर्ण लगती है, उनके लिए यह अनुपात चिंता की बात होती है। अगर भारत की एकता, अखंडता बनाए रखनी है तो यह जरूरी है कि यहां विभिन्न समुदायों के अनुपात में बहुत अधिक विषम वृद्धि न हो। जहां–जहां दुनिया में यह अनुपात बदलता है, वहां–वहां विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1947 में भारत विभाजन से पूर्व इसी प्रकार की स्थितियां बन गई थीं। कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होने के कारण वहां पृथक देश की मांग

उठी। यह खतरा अब फिर सर उठाने लगा है। भारत के कई क्षेत्रों में यह खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में भारतीय मूल के पंथावलम्बियों का अनुपात घट रहा है। पिछले पचास वर्षों में जनगणना के आंकडे देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि 1971 से 1991 और 1991 से 2001 में जनसांख्यिक अनुपात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बदला। इन दो दशकों में मुसलमानों का अनुपात बहुत तेजी से बदला। 2001 की जनगणना में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 36 प्रतिशत दर्ज की गई, हिन्दुओं की जनसख्या वृद्धि दर में कमी आई है और यह 20.3 प्रतिशत है।

भारतीय मूल के पंथावलम्बियों में उदासीनता

जब हिन्दू अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाये, तब हर दिशा में पतन होना स्वाभाविक था। 1981–1991 में जिस तेजी से भारतीय मूल के पथावलम्बियों का अनुपात घटना शुरू हुआ, उसका कारण स्पष्ट रूप से अपने प्रति उदासीनता का भाव है। यह प्रवृत्ति 2001 के आंकड़ों में और भी मुखर हुई है। हिन्दुओं का अनुपात घटने की प्रक्रिया और भी तेज हो रही है। यह बड़े संकट का संकेत है।

जब उसमें अपनी सभ्यता–संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागेगा तो वह खुद ही उठ खडा होगा। हममें अपनी सभ्यता के प्रति इतनी आस्था हो कि अपने बच्चों को पढा सकें कि हम क्या थे और क्या हैं? हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है? अभी तो हम इसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि बच्चें को क्या पढ़ाएं? आजादी के 50 साल बाद भी हम यह तय नहीं कर पाए कि अपने इतिहास को किस परिप्रेक्ष्य में देखना है। बच्चों को यह बताना है कि हमारा देश महान था या कि गुलाम, पराजित ही रहा। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन हम उस पूरे इतिहास को शर्मनाक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जो देश यह निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है, कहां पहुंचना है, वह आगे कैसे बढ़ेगा ? कल तक चीन हमारे जैसा ही था, आज वह कहां पहुंच गया है। लेकिन हम अभी दुविधा में ही फंसे हैं। लेकिन अब हिन्दु धीरे–धीरे अपने आपको अभिव्यक्त करने लगे हैं। उनमें धीरे–धीरे अपने धर्म के प्रति आस्था जाग रही है। हमारा नेतृत्व उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर पा रहा।

राजनीतिक कारण

राजनीतिज्ञों द्वारा मुस्लिमों और ईसाइयों को ज्यादा प्रश्रय देने के कारण जनसांख्यिक अनुपात में यह अंतर आया – यह कहना ठीक नहीं होगा। यहां की जनता ने सरकारें भी बदल कर देख लीं। लेकिन इससे सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन देखने में नहीं आया, जैसे परियर्तन की अपेक्षा है। वर्षों की पराजय और उपनिवेश बने रहने के बाद स्वतंत्र होने पर राष्ट्र–निर्माण के लिए हमें जो परिश्रम करना चाहिए था, वह नहीं किया। राष्ट्र–निर्माण का भाव हमारे भीतर जागा ही नहीं। यह लगन तभी जागती है जब हमारे भीतर अपनी सभ्यता के प्रति गौरव का भाव हो। हमने गौरवशाली अतीत को भूलने की कोशिश की। हमने यह भी भुला दिया कि हम एक महान सभ्यता के वाहक हैं, उसे पुनर्जीवित करना हमारा कर्तव्य है। ■

आह्वान

- क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित है?
- क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम है ?

यदि हां

- तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास किजिए, आप में क्षमता है कि कलम की नोंक से दुनियां का रूख बदलने की।
- अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली – 10007 को प्रेषित करें।

दो महानायक : लक्ष्य एक

डॉ० विजय सोनकर शास्त्री, पूर्व सांसद

डा. हेडगेवार जी ने आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के रूप में हिन्दू समाज के पुनः संगठन का एक सुन्दर रेखा चित्र बनाया और डॉ० अम्बेडकर जी ने हिन्दू समाज के अभिन्न किन्तु भेदभाव, ऊँच–निम्न, हीनता व तिरस्कार के शिकार दलित समाज को जागृत करके उस अति सुन्दर रेखाचित्र में रंग भरने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। डॉ० हेडगेवार और डॉ० अम्बेडकर का समकालीन होना यह प्रकृति के स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रतिफल है और प्रकृति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता ही है। अगर हम दोनों महापुरूषों के कर्तृत्व पर एक नजर डालें तो स्वतः वह लक्ष्य समझ सकेंगे।

आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार ने हिन्दू समाज समाज की दुर्दशा को देखा। ज्ञान–विज्ञान व आध्यात्मिक चिन्तन व परम वैभव को प्राप्त महान देश भारतवर्ष, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था; वह भेदभाव, ऊंच–निम्न, अमीर–गरीब, कुरीतियां, जड़ता इत्यादि के आधार पर विखंडित हो अपने ही दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। डॉ० हेडगेवार ने तब दृढ़ निश्चय किया कि हम मां के आंसू को पोछेंगे। हम मां भारती की पीड़ा को दूर करेंगे। मां की गोद में भेदभाव रहित त्याग व बलिदान के विचार से पुष्ट बच्चों की किलकारी गुंजेगी तभी मां का चित् प्रसन्न होगा। डॉ० हेडगेवार जी ने हिन्दू एकीकरण, हिन्दू संगठन, हिन्दू स्वाभिमान का चिन्तन और हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना जैसे उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित किया। वास्तव में उक्त संघ कार्य क्या बिना सामाजिक भेदभाव मिटे संभव है ? क्या ऊंच–निम्न की भावना के रहते हिन्दू समाज संगठित हो पायेगा ? क्या हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियां छूत–अछूत

प. पू. डॉ० हेडगेवार जयंती (9 अप्रैल) एवं डॉ० अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर विशेष

के भेद हिन्दू समाज के एकीकरण के स्वप्न को पूरा होने देंगे ? बिना इसकी चिंता किए डॉ० हेडगेवार अपनी कल्पना की तस्वीर बनाते चले गये। इस आस में कि प्रकृति किसी को अवश्य भेजेंगी, जो उनके द्वारा बना इस रेखाचित्र में रंग भरेगा।

परमपूजनीय मूकनायक राष्ट्रपुरूष भारतरत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर गरीबी, बदहाली, हीनता और तिरस्कृत जीवन जीने वाले उसी समाज में अवतरित हुए। अभाव व अपमान के मध्य डॉ० अम्बेडकर ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इनकी पीड़ा को दूर करूँगा। हिन्दू समाज के अभिन्न मजदूर एवं नारकीय जीवन यापन करने वाले अपने बंधुओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाऊँगा। डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का स्वर ऊँचा किया। इसका तात्पर्य था कि दलित समाज सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो। बिना स्वतंत्रता के समानता हो नहीं सकती और स्वतंत्रता एवं समानता के बिना बंधुता की बात करना औचित्यपूर्ण नहीं है। दलित समाज के उद्धारक के रूप में वह महान रंगकर्मी अपनी तूलिका से उस तस्वीर में रंग भरने लगा, जो स्वयं प्रकृति ही डॉ० हेडगेवार से रेखांकित करा रही थी।

डॉ० हेडगेवार का हिन्दू एकीकरण, हिन्दू संगठनों व हिन्दू स्वाभिमान का चिंतन, दलितोत्थान के बिना संभव नहीं था। डॉक्टर साहब का मानना था कि समस्त हिन्दू समाज विखंडित हो अपनी दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पीछे उनका यही मंतव्य था कि हिन्दू संगठित हो। हिन्दू संगठन व उत्थान के लिए संघ ने कार्य करना प्रारंभ किया, जो कालान्तर में यह देश का सबसे बड़ा सुधारवादी संगठन बना। उसके अनेकानेक अनुसांगिक संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। हिन्दू राष्ट्र की रूपरेखा के साथ इस राष्ट्र के पास परमवैभव की अपेक्षा की गई। परमवैभव का तात्पर्य देश की भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उत्सर्ग से माना गया है।

इसलिए परमवैभव हेतु हिन्दुत्व का पूर्ण उद्‌भव व उत्थान अति आवश्यक है और यह दलितोत्थान का पूरक है।

इसी प्रकार डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के उत्थान पर ही राष्ट्र का उत्थान निर्भर करता है। दलित समस्या दलितों की समस्या न होकर तथाकथित उच्च समाज की समस्या है। दलितों के साथ भेदभाव व अस्पृश्यता दलितों की नहीं वरन् तथाकथित उच्च जाति के कहे जाने वाले विकृत मानसिकता के लोगों की समस्या है। दलितों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहारों के लिए प्राचीन व्यवस्था के रूप में अवस्थित संस्थाएं, कुरीतियां, भेदभाव, अस्पृश्यता व सामाजिक व्यवस्था के अनुसार दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेवार कारकों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा तीक्ष्ण प्रहार डॉ० अम्बेडकर के संघर्ष का एक सफल परिणाम है। डॉ० अम्बेडकर सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में रहे। प्रारम्भ काल में डॉ० हेडगेवार से उनके लगातार संपर्क थे। वे संघ के कार्यक्रमों व उत्सवों में जाते भी रहे। समय–समय पर उनके सुझाव पर संघ कार्यक्षेत्र में अमल भी किया जाता रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गोलवरकर जी, श्रद्धेय राष्ट्रऋषि के रूप में स्थापित दन्तोपन्त ठेगड़ी जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि लोगों के भी सम्पर्क में जीवन के आखिरी दिनों तक रहे।

आज तेजी से समयचक्र अपनी धुरी पर घूम रहा है। डॉ० हेडगेवार व डॉ० अम्बेडकर दैहिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु लगभग 80 वर्ष के इस अन्तराल में डाक्टर हेडगेवार जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दलितोत्थान के संघर्ष का व्यापक असर परिलक्षित होता है। आज हिन्दुत्व के उत्थान व पुनर्स्थापना के संदर्भ में डॉ० हेडगेवार जी को शीर्षस्थ रूप में और डॉ० अम्बेडकर जी को दलितों के एकमात्र पथ–प्रदर्शक एवं भगवान के रूप में स्मरण किया जा रहा है। डॉ० हेडगेवार जी ने अपेक्षा की कि हिन्दुओं में जिन्हें आज दलित की संज्ञा दे दी गई है, उनके साथ सद्व्यवहार एवं उन्हें पूर्णरूपेण सम्मानित करके उनका अधिकार उन्हें देकर हिन्दू समाज को समरस बनाकर हिन्दू को संगठित करत हुए उन्हें हिन्दू हित व एकीकरण के मुद्दे पर एक मंच पर लाया जाय। इसी प्रकार डॉ० अम्बेडकर जी ने भी हिन्दू समाज के तथाकथित उच्चवर्गीय लोगों से अपेक्षा की कि दलित वर्ग को सामाजिक दासता से मुक्त करके उन्हें समानता का अवसर प्रदान किया जाय और दासता से मुक्त एवं सामाजिक समरसता के बाद ही सामाजिक बंधुता यानि भाई–चारा स्थापित हो सकेगा। ऐसे में डॉ० हेडगेवार जी की अपेक्षा तथा कथित दलित समज से एवं डॉ० अम्बेडकर जी की अपेक्षा तथाकथित सवर्ण समाज से जो वांछित है उस पर अब विचार ही नहीं सुस्पष्ट एवं आत्म पवित्रता के साथ पालन करने की आवश्यकता है।

आज तेजी से समयचक्र अपनी धुरी पर घूम रहा है। डॉ० हेडगेवार व डॉ० अम्बेडकर दैहिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु लगभग 80 वर्ष के इस अन्तराल में डाक्टर हेडगेवार जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दलितोत्थान के संघर्ष का व्यापक असर परिलक्षित होता है।

डॉ० हेडगेवार जी के संघ कार्य को उनके देहावसान के बाद आज भी अनवरत संचालित किया जा रहा है एवं डॉ० अम्बेडकर जी के विचारों को उनके हजारों–हजार अनुयायियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है किन्तु हिन्दू विरोधी ताकतें संघ कार्य को अवरूद्ध एवं डॉ० अम्बेडकर जी मिशन को विभ्रमित करने का व्यापक षडयंत्र रच रही हैं। अब तो समाज को चिंता नहीं बल्कि यह चिंतन करना होगा कि दोनों महापुरूषों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मन को साफ करके और दिल खोलकर सहृदयता, उदारता, बुद्धिमत्ता एवं ईमानदारी से स्वःसेवा की भावना को प्रस्तुत करते हुए समाज का अभिन्न भाग बन जाना है। तभी डॉ० हेडगेवार के रेखाचित्र को डॉ० अम्बेडकर के तूलिका से रंगा जा सकेगा। डॉ० हेडगेवार ने जो शरीर रचना की है, उसमें डॉ० अम्बेडकर के विचार रूपी आत्मा को स्थापित करके हिन्दू समाज के अधिष्ठान को पुष्ट करना है। काश यह देखा जा सकता कि डॉ० हेडगेवार जी के द्वारा बनाये जा रहे रेखाचित्र को डॉ० अम्बेडकर जी के संघर्ष रूपी तूलिका से कैसे रंगा जायेगा। दोनों महानायकों के लक्ष्य को अब हमें एक ही देखना होगा। ■

QUEST FOR JUSTICE

'Struggle of Rai university students for their degrees'

When education becomes a means of earning money then this is what happens, what is happening now to numerous students of Rai University. Students took admissions with numerous hopes & big dreams of making a bright future; but their future hangs in the middle of a sea of darkness.

A girl from Rai University participating in an agitation led by ABVP at ITO.

On the 11th of Feb, The Hon'ble Supreme Court responded to the writ petition filed by Prof. Yashpal & closed down all the 'Degree Shops' which were established under the Chhattisgarh University Act of the former Ajit Jogi Government. Former UGC Chairman Prof.Yashpal raised question on the validity & integrity of the section (5) & (6) of the act according to which a university established in Chhattisgarh was authorized to open it's off campuses in other states as well. The apex court in its judgment declared section (5) & (6) of the act as ultra vires the constitution & thus declared them null & void.

The judgment affected 108 Universities & Rai University was prominent among them. Although the judgment protected the interest of 34,000 affected students & directed the institutions to seek affiliation from the existing state universities. Many of these institutions immediately succumbed to the Supreme Court judgment & took required remedial measures. But, the Selfish Rai University Management shattered the hopes & dreams of 12,000 Rai students & did not even accept the offer from GGSIP University, Delhi, which was ready to grant affiliation under relaxed norms, just because it would affect their profitable status.

In the meanwhile the 7,500 Rai students of Delhi & NCR were not sure whether they would get a Valid, Regular Degree or not. After making many in house protests & dharnas at Jantar Mantar, the students decided to knock the doors of the Concerned Government authorities & in the process posted their memorandum to the Hon'ble President, the Prime Minister & met Mr. Arjun Singh (Central HRD Minister), Ms. Sheila Dixit (CM, Delhi). But all their pleas fell into deaf ears.

While the Rai Management closed its campuses, terminated

90% of teaching & non teaching staff & asked the students to withdraw their admissions. Nobody was ready to listen to the plight of the students, who are paying the ultimate price. The Media seemed always busy with Glamour, Sports, PAGE 3 & monetary gain from RAI Advertisements. The Hon'ble Politicians are always busy with their political equations. And the Hon'ble President of India seemed unapproachable. Then the helpless students got the only helping hand from AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD.

With a moral support & personal presence of Manoj Verma ji & Mr. Nakul Bhardwaj from ABVP the students restarted their agitation on a large scale & went for a Hunger Strike at Jantar Mantar from the 16th to 21st of March. During which 2 students were admitted to the RML hospital due to their worsened condition. By the influence of this strike various Media & other student organizations came forward to listen to the students but ultimately to no avail. On the other hand the Rai Management continued to befool students with their fake assurances & never came to talk to the protesting students. The management always claimed that it would reinstate their University status & have got affiliation from Pt. Ravi Shanker Shukla University in Raipur.

With Hunger Strike on place the students under the able guidance of Manoj Verma Ji, met Mr. Raman Singh (CM, Chhattisgarh) who brought into light the stated facts & made it clear that the affected institutes have to get affiliated to their respective state Universities. And if the institute does not comply, the thousands of students enrolled in RU would only land with a DLP degree without any approvals such as UGC, AICTE etc. & the Degrees would be worthless.

With no fruitful results in hand, the Rai University students in association with ABVP were forced to lift their agitation to the next level, and on 6th April hundreds of students staged a major ROAD BLOCK at ITO which lasted for about 45 minutes, resulting in a big chaos in the traffic run. To overcome the situation Police CHARGED LATHI & arrested most of the students. The protest was led by Mr. Nakul Bhardwaj, Mr. Sunder Dager, Mr. Anubhav Sapra & Mr. Gaurav Khari from ABVP & Mr. Amrish, Ms. Roomi Banerjee, Mr. Krishna Kant, Mr. Amit Pandey & Ms. Katyayani from Rai University who got arrested & later were released. In the process the students got assurances from the Concerned Govt. Authorities & Mr. Nakul Bhardwaj made it clear that they would fierce their agitation if their demands for a valid degree are not met soon.

Continuing their on road demonstrations students staged another major ROAD BLOCK on 23rd April, at the. busy Mathura Road in front of the university office, the jam lasted for about an hour & the agitated students BURNT TYRES & voiced their demands for immediate action. Again the Police had to use force, LATHI CHARGE & arrested 12 students, who were released after 10 Hrs of detention.

Even after 3 months of struggle & running from pillar to post, the suffering students holding the hands of ABVP hope that uncertainty looming over their future would come to an end, and they will get back to their books from their on road demonstration. And their Quest for a valid degree, will get an answer!!! ■

परिषद गतिविधियां

''आधुनिक शिक्षा : युवा और राष्ट्र पुनर्निर्माण'' विषय पर संगोष्ठी

इदौर, 13 अप्रैल, 2005। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प तकनीकी शिक्षण विद्यार्थी परिषद द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमो के छात्रों की संगोष्ठी दे०अ०वि०वि० के प्रबंध अध्ययन संस्थान सभागृह में आयोजित की गई। विषय था – 'आधुनिक शिक्षा : युवा और राष्ट्र पुनर्निर्माण।' कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री कैलाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में समाज के अन्य घटक के साथ–साथ छात्र युवाओं का सहयोग भी नितांत अपेक्षित है। संगोष्ठी को ग्वालियर विभाग संगठन मंत्री श्री संजय ठाकुर, महानगर अध्यक्ष श्री महेश पालीवाल और मंत्री श्री जयदीप सिंह गौड ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी का संचालन श्री सुमित त्रिवेदी ने किया एवं आभार श्री कृष्ण ने माना।

कोटा में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता 'अभिव्यक्ति' सम्पन्न

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा में गत 19–20 मार्च को राज्य स्तरीय तकनीकी मॉडल प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता "अभिव्यक्ति – 2005" आयोजित की गई। इसका आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राजस्थान प्रदेश का प्रकल्प तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया। राज्यभर के 15 अभियांत्रिकी एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 220 छात्र–छात्राओं ने उसमें भाग लिया तथा 79 मॉडल प्रस्तुत किये गये।

सिविल वर्ग में सी.टी.ए.ई. उदयपुर के "मॉडल सोलर अम्ब्रेला" को प्रथम तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर के "ई – बिजूका विद ऑटो इरीगेशन" को द्वितीय पुरस्कार मिला। मैकेनिकल वर्ग में इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा के "अर्थक्वेक रजिस्टेंट" को प्रथम तथा कोटा कॉलेज के ही "सेल्फ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस" को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इलैक्ट्रिकल वर्ग में जी.आई.टी., जयपुर के "इलैक्ट्रिकल ट्रेक ट्रेसिंग रोबोट" को प्रथम तथा इंजिनियरिंग कॉलेज, कोटा के वायरलैस कम्यूनिकेशन को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

निजी इंजीनियरिंग व व्यावसायिक कॉलेजों की फीस वृद्धि का विरोध

इंदौर 4 मई, 2005। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फीस निर्धारण समिति द्वारा तय की गई इंजीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक कॉलेजों की फीस वृद्धि का विरोध किया है।

अ०भा०वि०प० के प्रांतीय मंत्री श्री भरत पारख ने कहा है कि न्यायमूर्ति श्री सचीन्द्र द्विवेदी ने जो अपना अंतिम आदेश सुनाया है, वह छात्र विरोधी एवं शिक्षा को व्यावसायिकरण की ओर ले जाने वाला है। यह निजी कॉलेज संचालकों के पक्ष में है एवं इससे शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस विषय में विद्यार्थी परिषद का मानना है कि समिति के अंतरिम आदेश को ही लागू रखा जाए एवं राज्य शासन नई समिति गठित कर पुनः फीस निर्धारण करें अन्यथा वर्तमान समिति का कार्यकाल बढ़ाकरफीस वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए एवं शेष रहे निजी मेडिकल कॉलेजों की भी छात्रहित में फीस निर्धारित हो। अंतिम आदेश के विषय में विद्यार्थी परिषद का मानना है कि पहली श्रेणी मे रखे गए निजी कॉलेज एवं पाठयक्रम, जिनकी फीस बढ़ाई गई है, वह शिक्षा के बाजारीकरण एवं व्यावसायिकरण को बढ़ावा देने वाला है।

परिषद का यह भी कहना है कि पहली श्रेणी के निजी कॉलेजों की तुलना यदि महाराष्ट्र के निजी कॉलेजों से की जाए तो पता लगेगा कि पहली श्रेणी के कॉलेजों की फीस महाराष्ट्र के निजी कॉलेजों की तुलना में कही अधिक है। विद्यार्थी परिषद का इस विषय में यह भी मानना है कि सभी निजी कॉलेजों में समान शुल्क संरचना होनी चाहिए, जो छात्रहित एवं शिक्षा के व्यावसायिकरण को रोकने वाली हो।

जम्मू में बी०एड० पाठयक्रम में हिन्दी माध्यम की मांग को लेकर छात्रों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जम्मू–कश्मीर प्रदेश ने बी०एड० पाठयक्रम में विकल्प के रूप में हिन्दी माध्यम की मांग को लेकर 14 मार्च, 2005 को जम्मू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना और विशाल छात्र प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन में छात्र–छात्राओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

धरने पर बैठे छात्र–छात्राओं ने कहा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में सम्पूर्ण भारत में प्रतिष्ठित है तथा देश के हर जन को इसका सम्मान करना चाहिए। बी०एड० की पढ़ाई करनेवाले अधिकांश छात्र हिन्दी माध्यम की जरूरत महसूस करते है और इसी को आधार मानते हुए छात्रों के समक्ष हिन्दी माध्यम विकल्प के रूप में अवश्य होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस दिशा में अविलंब सार्थक प्रयास करे अन्यथा विद्यार्थी परिषद और अधिक मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढाने के लिए तैयार है। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता विद्यार्थी परिषद के जम्मू–कश्मीर प्रांत अध्यक्ष श्री विनय शर्मा ने की। कार्यक्रम में अभाविप के प्रांत मंत्री आदर्श कुमार, सुरेश मंगोत्रा, जम्मू इकाई मंत्री पृथ्वी सिंह, रोहन नंदा, निशांत, अनिता मंगोत्रा सहित अनेक छात्र नेताओं ने भाग लिया।

विद्यार्थी परिषद इस संबंध में चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, जिसमें छात्रों ने बढ–चढ़कर अपना विरोध दर्ज किया। महामहिम राज्यपाल को भी उक्त मांग के आलोक में ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल महोदय ने परिषद् कार्यकर्ताओं को सार्थक कार्यवाही करने का भरोसा दिया। इसके पश्चात् बी०एड० के तीनों कॉलेजों के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रैली निकाली और जिला उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। इस प्रभावी आंदोलन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और जल्द ही इसके अच्छे परिणाम आयेंगे, ऐसा वातावरण भी वि०वि० परिसर में स्पष्ट दिखाई देने लगा है।

जोधपुर में 'रोजगार सृजन' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राजस्थान प्रदेश ने जोधपुर में 7 और 8 मई, 2005 को 'रोजगार सृजन में सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। संगोष्ठी की मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान की अध्यक्ष श्रीमती सरोज कुमारी थी। विशिष्ट अतिथि के नाते सहकार भारती, जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष श्री शुद्धराज लोढ़ा ने उपस्थित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गोपाल आर्य थे। श्री आर्य ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि रोजगार सृजन में सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संगठनों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राजकीय क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं लगातार कम हो रहे है। ऐसी परिस्थिति में युवकों को स्वयं आगे आकर अथवा स्वयं सहायता समूह बनाकर उद्योग लगाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर विषय बल दिए जाने की जरूरत को उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवकों के समक्ष बेरोजगारी की विकराल समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बेराजगारी के कारण कई गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने सदैव "रोजगार" के सवाल को लेकर छात्र आंदोलनों के माध्यम से सरकार पर दबाव निर्माण करने का प्रयास किया है।

दो दिन चले इस संगोष्ठी में कुछ छह सत्र निम्न विषय पर आयोजित किए गए : उद्यमिता एवं स्वरोजगार : एक आवश्यकता, सहकारिता कार्यक्षेत्र : एक संभावना, पंजीकरण प्रक्रिया एवं संवैधानिक नियम : एक जानकारी, सरकारी नीतियां एव वित्तीय प्रबंधन : एक अवलोकन, गैर सरकारी संगठन : कार्यक्षेत्र एवं संभावना और स्वयं सहायता समूह : ग्रामीण विकास की अवधारणा। "संगोष्ठी में "नाबार्ड एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन" विषय पर विशेष परिचर्चा सत्र आयोजित की गई। प्रत्येक सत्र को विषय से संबंधित गहन जानकार 23 वक्ताओं ने संबोधित किया।

संगोष्ठी की अध्यक्षता सहकार भारती के राजस्थान प्रांत अध्यक्ष श्री मुकेश मोदी ने की। संगोष्ठी में उपस्थित प्रतिनिधियों की गहन रूचि व विचार–विमर्श के स्वरूप से यह बात स्पष्ट सामने आई कि यह कार्यक्रम राजस्थान की विकास के दिशा में निःसंदेह एक मील का पत्थर साबित होगा।

सिक्किम में पूर्व सील प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गान्तोक द्वारा सिक्किम व दार्जिलिंग के पूर्व SEIL कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 16–17 अप्रैल 2005 को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में आठ स्थान से 56 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन इस क्षेत्र के प्रथम SEIL TOUR में से एक सदस्य श्री धीरज राई जी ने किया। दार्जिलिंग जिला के कालिम्पोंग से प्रथम SEIL TOUR में 1989–90 में आठ सदस्य गए थे।

प्रथम सत्र में 1990 के सदस्यों से लेकर 2003 के सदस्यों ने अपने सुनहरे पलों को याद किया, श्री कमल शर्मा, श्री विनोद छेत्री, कु० अन्जना राई, कु० दावी सुब्बा आदि सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि आज हमको इस क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि SEIL TOUR से पहले हम कुएं के मेढक जैसे थे, जो मात्र इस क्षेत्र के बारे में सोचते थे, अब देश का विशाल विचार हमारे समझ में आया है और हमको इस विचार के लिए काम करना है।

श्री लक्ष्मी नारायण भाला, क्षेत्रीय सगठन मंत्री, विद्या भारती ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज की शिक्षा हमको अपनी संस्कृति की जडों से काटनेवाली है। यह शिक्षा युवाओं का भला नहीं कर सकती। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सिक्किम व दार्जिलिंग जिला में चल रहे संगठनों के गतिविधियों की जानकारी दी।

कार्यक्रम का समारोप, श्री पी० चन्द्रशेखर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद ने किया। इस अवसर पर मा० सुनील पद गोस्वामी जी क्षेत्रीय प्रचारक का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपने समापन भाषण में श्री शेखर ने पूर्व SEIL सदस्यों से वर्तमान समय में विद्यार्थी परिषद एवं सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुरोध किया, साथ ही उन्होंने कार्यपद्धति को प्रत्येक ईकाई में मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमको बुराईयों के विरूद्ध लम्बे समय तक लड़नेवाला एक जिम्मेवार नागरिक तैयार करने के लिए काम करना है। इस अवसर पर रा.स्व. संघ के प्रांत प्रचारक उत्तरवंग श्री अद्वैत चरन दत्त, सिक्किम भाजपा अध्यक्ष श्री एच आर प्रधान, प.बं. विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री श्री अमिताभ चक्रवती सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर विद्यार्थी परिषद् का मत

राजस्थान उच्च न्यायालय के 5 मई को हुये निर्णय के अनुसार छात्र संघ, शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के चुनावों पर रोक के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी परिषद, राजस्थान प्रदेश कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि छात्र संघ चुनावों में रोक के बजाय व्यापक सुधार की आवश्यकता विद्यार्थी परिषद विगत वर्षों से अनुभव कर रही है। छात्र संघ चुनावों के दौरान बिगड़ते शैक्षिक वातावरण, छात्र संघों के कार्यक्रम व अधिकार, प्रत्याशी की योग्यता को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी परिषद् व्यापक सुधार की पहल करती रही है। चुनावों पर रोक लगने से बढ़ती हिंसा, जातिवाद, गिरता हुआ शैक्षणिक स्तर, गुरू–शिष्य के संबंधों में बढ़ती दूरी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इन समस्याओं का समाधान सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। चुनावों पर रोक के कारण छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु नेतृत्व की आवश्यकता है। परिषद इस निर्णय से छात्रों एवं शिक्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रदेश कार्यकारी परिषद में चर्चा करेगी एवं आवश्यक हुआ तो न्यायालय में जायेगी। ■

प्रवेश 2005-06

जामिया मिलिया इस्लामिया

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

- नैचुरल साइंस फैकल्टी 2/6/2005
- सोशल साइंस फैकल्टी – 7/6/2005
- ह्यूमैनिटीज एड लैंगुएज फैकल्टी – 6/6/2005
- फैकल्टी ऑफ लॉ – 31/05/2005
- सुपरन्यूमेरीरी सीट्स इन ऑल फैकल्टीज – 1/7/2005

फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

प्रॉस्पेक्टस 2005–2006

- बी.ई (सांध्य कोर्स) – 30/9/2005
- डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग (सांध्य कोर्स) – 30/9/2005
- एमबीए (सांध्य कोर्स) – 30/9/2005
- बी.टेक/बी.आर्किटेक्चर – 29/4/2005
- डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग – 29/4/2005

फॉर्म डाउनलोड करने के संदर्भ में :

वेब डाउनलोड फॉर्म के लिए फॉर्म संख्या अनिवार्य नहीं है।

10X23 सेमी लिफाफे पर 23 रूपये का पोस्टेज स्टैंप और खुद का पता लिख कर आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजें–

द डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दल्ली – 1110025 (भारत)

एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2005–2006 में दिये गये नियमानुसार ही आवेदन पत्र भरें।

वेबसाइट : http://jmi.nic.in

दिल्ली विश्वविद्यालय

स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने हेतु

- आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की तिथि – 1 जून से 15 जून (प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक)
- पहली कट ऑफ सूची – 25 जून
- शुल्क जमा करने की तिथि – 26 जून से 29 जून (प्रात 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक)
- दूसरी कट ऑफ सूची – 30 जून
- शुल्क जमा करने की तिथि – 1 जुलाई से 4 जुलाई (समय पूर्ववत्)
- तीसरी कट ऑफ सूची – 5 जुलाई
- शुल्क जमा करने की तिथि – 6 जुलाई से 8 जुलाई (समय पूर्ववत्)
- चौथी कट ऑफ सूची (जरूरी हुई तो) – 9 जुलाई
- शुल्क जमा करने की तिथि – 11 जुलाई से 13 जुलाई (समय पूर्ववत्)
- SC/ST छात्रों के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं जमा कराने की तिथि – 1 जून से 7 जून
- पहली सूची (स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, नार्थ कैम्पस) – 1 जुलाई
- फीजिकली चैलेंज्ड छात्रों का पंजीकरण एवं आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने की तिथि (DSW Office – 1 जून से 15 जून
- पहली सूची – 1 जुलाई।
- नया आई सी आर फॉर्म 20 रूपये में मिलेंगे।
- फॉर्म की खासियत यह होगी कि कॉलेजों की तरह इसके साथ तमाम सूचनाओं से लैस प्रॉस्पैक्ट्स भी मिलेगा।

Website : www.du.nic.in

प. उत्तर प्रदेश विद्यार्थी परिषद की ओर से शैक्षिक समस्या के आलोक में उ. प्र. के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को ज्ञापन सौंपते राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री अतुल कोठारी एवं राष्ट्रीय मंत्री श्री धर्मपाल।

सिक्किम प्रांत द्वारा गंगटोक में आयोजित पूर्व सील प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री पी. चन्द्रशेखर।

अभाविप, राजस्थान प्रांत की ओर से जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार सृजन कार्यशाला को सम्बोधित करती राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सरोज कुमारी।

हिमाचल प्रदेश विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन 'स्मृति 2005' को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर।

छात्रशक्ति - राष्ट्रशक्ति